



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 2018/वैशाख 13, 1940

No. 162]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 2018/VAISAKHA 13, 1940

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2018

प्रकरण सं. 06/2018

(निर्णायक समीक्षा जांच)

विषय – यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाइलीन क्लोराइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

फा. सं. 7/15/2018-डीजीएडी.— मैसर्स गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स कैमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात आवेदनकर्ता अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमरीका और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाइलीन क्लोराइड (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. ऊपर उल्लिखित याचिकाकर्ताओं ने ईयू और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के निरंतर पाटन और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के निरंतर पाटन की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है और इन देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

3. आवेदकों ने आगे तर्क दिया है कि यद्यपि पीओआई में कोरिया गणराज्य से कोई आयात नहीं हुए हैं तथापि पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है क्योंकि पीओआई से पहले कोरिया से आयात पाटित कीमतों पर हुए थे।

क. पृष्ठभूमि

4. यतः उक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 4 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं 14/19/2012-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ (ईयू), संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाइलीन क्लोराइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की थी। प्रारंभिक जाँच परिणाम दिनांक 6 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किए गए और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं 24/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा अंतिम शुल्क लगाया गया। तत्पश्चात् प्राधिकारी ने 2 अप्रैल, 2014 को अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जिसमें संबद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 मई, 2014 की अधिसूचना सं 24/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'मिथाइलीन क्लोराइड' है जैसे वह मूल जांच में था। इसे डिक्लोरोमिथेन और मिथाइलीन डाइक्लोराइड (एमडीसी) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका आण्विक फार्मूला सीएच₂सीएल₂ होता है। यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसकी ईथर की तरह की सुहावनी सुगंध होती है और इसका प्रयोग विलायक के रूप में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। प्रयोग की अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत यह ज्वलनशील नहीं है पर अधिक गर्म करने पर यह जल सकता है। मिथाइलीन क्लोराइड उच्च ताप पर जहरीली गैसें बनाते हुए डिकम्पोज हो सकता है। यह अनेक विलायकों के साथ पूरी तरह से मिल जाता है।

6. एमडीसी एक विलायक है और उसका प्रयोग पालीकार्बोनेट और फेनोलिक रेजिंस, रेयन यार्न, भेषजों, कृषि और सुगंध रसायनों के विनिर्माण में होता है। इसका प्रयोग खाद्य वसा, कोकोआ, बटर और सत्वों के लिए निष्कर्षक के रूप में भी होता है। मिथाइलीन क्लोराइड के उत्पादन की दो प्रौद्योगिकियां हैं—मिथेन रूट और मेथेनॉल रूट। दोनों तरीकों से उत्पादित उत्पाद में अनिवार्य रूप से समान तकनीकी विशेषताएं होती हैं।

7. मिथाइलीन क्लोराइड को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 (कार्बनिक रसायन) के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष 29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु मानते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मैसर्स गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। देश में मिथाइलीन क्लोराइड के तीन अन्य उत्पादक भी हैं – टीजीवी एसआरएएसी लि. (पहले श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड अलाइड कैमिकल्स लि.), गुजरात अल्कलाइ एंड कैमिकल्स लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड। अन्य उत्पादकों में से टीजीवी एसआरएएसी लि. ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह घोषण की है कि उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात नहीं किया है, और न ही वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से उनका कोई संबंध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "स्थिति" की जरूरत को पूरा करते हैं और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" हैं।

घ. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

10. आवेदकों ने बताया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया था। यद्यपि उन्हें यूरोप में आईसीआईएस एलओआर प्राइसिंगरिपोर्ट से प्रचलित कीमतों संबंधी सूचना मिल पाई तथापि उन्हें यूएसए में प्रचलित कीमतों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई। आवेदकों ने आईसीआईएस एलओआर रिपोर्ट के

अनुसार ईयू में प्रचलित कीमतों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ईयू में प्रचलित कीमतों को यूएसए में प्रचलित कीमतों के रूप में अपनाया है।

प्राधिकारी ने आवेदकों के दावों की जांच की है और नोट करते हैं कि उक्त रिपोर्टों में उद्धरित कीमतों को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के अनंतिम निर्धारण के लिए प्रथम दृष्टया अपनाया जा सकता है।

11. आवेदकों ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत का दावा किया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए, सीआईएफ आधार पर निर्यात कीमतों को कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों, अंतर्देशीय मालभाड़े और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

ड. पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि ईयू और यूएसए में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है।

च. घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति और क्षति के जारी रहने की संभावना

13. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर क्षति के जारी रहने और क्षति के जारी रहने की संभावना का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी प्रथम दृष्टया पाते हैं कि घरेलू उद्योग को ईयू और यूएसए से निर्यातकों द्वारा लगातार पाटन के परिणामस्वरूप कीमत क्षति होना जारी है।

छ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

14. और यतः, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और इस निष्कर्ष से कि यूरोपीय संघ और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को उचित ठहराता है, प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके।

15. इसके अलावा, चूंकि पीओआई में कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के कोई आयात नहीं हुए हैं और परिणामस्वरूप कोरियाई उत्पादकों द्वारा वर्तमान पाटन का कोई साक्ष्य नहीं है, तदनुसार कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत नहीं की जा रही है।

ज. शामिल देश

16. अतः, जिन देशों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की गई है ईयू और यूएसए (जिन्हें संबद्ध देश कहा गया है) हैं।

झ. जांच अवधि (पीओआई)

17. आवेदकों द्वारा जाँच अवधि के रूप में 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 (12 महीने) की अवधि का प्रस्ताव किया गया है। क्षति का विश्लेषण करने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जाँच की प्रस्तावित अवधि पर विचार किया गया है।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ब. सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

20. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और विहित प्रपत्र (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) में प्रस्तुत कर सकता है।

ट. समय-सीमा

21. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध जांच शुरूआत की सूचना देने वाले प्राधिकारी के पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पत्र पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे जांच शुरूआत की सूचना देने वाले प्राधिकारी के पत्र के जारी होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रभावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. यदि प्रभावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितवद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितवद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

डू असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2018

Case No. 06/2018

(Sunset Review Investigation)

Subject : Initiation of Sunset Review Investigation of anti-dumping duty concerning imports of Methylene Chloride originating in or exported from the European Union and the United States of America.

F. No. 7/15/2018- DGAD.—M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd. and M/s Chemplast Sanmar Ltd. (hereinafter referred to as the applicants or petitioners) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping sunset review investigation concerning imports of Methylene Chloride (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from European Union, the United States of America and Korea RP.

2. The above referred petitioners have filed a duly substantiated application alleging continued dumping of the subject goods, originating in or exported from the EU and the USA and likelihood of continuation of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods from these countries.

3. The applicants have further argued that though there were no imports from Korea in the POI there is likelihood of recurrence of dumping and injury thereof as the imports from Korea before the POI were at dumped prices.

A. Background

4. Whereas, having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) had initiated an antidumping investigation concerning imports of Methylene Chloride originating in or exported from the European Union ("EU"), the United States of America ("USA") and Korea RP, vide Notification No. 14/19/2012-DGAD dated 4th April, 2013. The Preliminary Findings were notified on 6th September, 2013 and the provisional duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 24/2013 - Cus (ADD), dated October 21, 2013. The Authority had thereafter issued final findings on 2nd April, 2014 recommending definitive antidumping duty on the subject imports. The definitive anti dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 24/2014-Cus (ADD), dated May 21, 2014.

B. Product under consideration and Like article

5. The product under consideration in the present investigation is “Methylene Chloride” as it was in the original investigation. It is also known as Dichloromethane and Methylene Dichloride (MDC). It is an organic compound with molecular formula CH_2Cl_2 . It is a colorless liquid with sweetish ether-like odour, and is used as a solvent predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use. However, it can burn if strongly heated. Methylene chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents.

6. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance chemicals. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences. There are two technologies for production of Methylene Chloride - Methane route and Methanol route. The product produced through both the routes has essentially similar technical characteristics.

7. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

8. The applicants have claimed that subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject country are like articles within the meaning of the anti-dumping Rules. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry and the subject goods are comparable in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry and Standing

9. The application has been jointly filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. and Chemplast Sanmar Ltd. There are three other producers of Methylene Chloride in the Country- TGV SRAAC Ltd. (formerly Sree Rayalaseema Alkalies and Allied Chemicals Ltd.) Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and SRF Ltd. Among other producers, TGV SRAAC Ltd. has supported the present application. As per information furnished in the application, the production of the applicants accounts for major proportion of the total domestic production of the subject goods. Further, the applicants have declared that they have neither imported the product under consideration from the subject countries, nor are they related to any exporter of the product under consideration in the subject countries or to an importer of subject goods in India. The Authority notes that the applicants fulfil the requisite criteria to satisfy the requirements of “standing” under Rule 5 of the AD Rules and therefore constitute domestic industry, as required under the AD Rules.

D. Normal Value and Export Price

10. The applicants have submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries. While they could get information on prices prevailing in Europe from ICIS LOR Pricing report, they could not get any information about the prices prevailing in USA. The applicants have furnished the prices of subject goods prevailing in EU as per ICIS LOR report. They have adopted the price prevailing in the EU as the price prevailing in USA. The Authority has examined the claim of the applicants and notes that the prices quoted in above reports can prima facie be taken for provisional determination of normal value of the subject goods in the subject countries for the purpose of initiation of investigation.

11. The applicants have claimed the export price as per DGCIS data. For fair comparison between the normal value and export price, the export prices at CIF basis have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges in order to determine the net export price at ex-factory level.

E. Dumping Margin

12. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the EU and the USA are higher than the ex-factory export price.

F. Continued Injury to the domestic industry and likelihood of continuation of injury

13. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of continued injury and likelihood of continuation of injury. The Authority prima facie finds that the domestic injury continues to suffer price injury as a result of continued dumping by the exporters from the EU and the USA.

G. Initiation of the Review

14. And Whereas, in view of the duly substantiated application filed in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules and on finding that prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from European Union & USA, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates sunset review investigation to review the need for continuation of the antidumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

15. Further, since there were no imports of the subject goods from Korea RP in the POI and consequently no evidence of current dumping by the Korean producers, the anti-dumping investigation accordingly is not being initiated concerning imports originating in or exported from Korea RP.

H. Countries involved

16. Therefore, the countries against which present sunset review investigation is initiated are EU and USA (referred to as the "subject countries").

I. Period of investigation (POI)

17. The Applicants have proposed the period from 1st January, 2017 to 31st December, 2017 (12 months) as the period of investigation. For the purpose of analyzing injury, the data of previous three financial years, i.e. 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the proposed period of investigation has been considered.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. Submission of Information

19. The known producers and exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi -110001.**

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form (downloadable from the website of the Authority at www.dgtr.gov.in) and manner within the time limit set out below.

K. Time Limit

21. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's

application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation.

L. Submission of information on confidential basis/Non-Confidential basis

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of public file

29. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

30. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority